



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 27 दिसम्बर, 2006/6 पौष, 1928

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-2, 27 दिसम्बर, 2006

संख्या वि० स०-विधायन-गवर्नमेंट बिल/1-60/2006.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख-सुविधाएं) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 32) जो आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2006 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित

हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाजटा,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

**हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां,
विशेषाधिकार और सुख-सुविधाएं) विधेयक, 2006**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में संसदीय सचिवों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियों, विशेषाधिकारों और सुख-सुविधाओं का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव संक्षिप्त (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख-सुविधाएं) अधिनियम, नाम। 2006 है।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न परिभाषाएं हो,—
 - (क) "मुख्य मन्त्री" से हिमाचल प्रदेश का मुख्य मन्त्री अभिप्रेत है;
 - (ख) "सदस्य" से हिमाचल प्रदेश विधान सभा का सदस्य अभिप्रेत है;
 - (ग) "अधिसूचना" से समुचित प्राधिकार के अधीन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
 - (घ) "संसदीय सचिव" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन संसदीय सचिव या मुख्य संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा का सदस्य अभिप्रेत है;
 - (ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और
 - (च) "विनिर्दिष्ट" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है।

नियुक्ति।

3. मुख्य मन्त्री, संसदीय सचिवों को ऐसी संख्या में नियुक्त कर सकेगा और उनमें से प्रत्येक को ऐसे कर्त्तव्यों और कृत्य सौंप सकेगा, जैसे वह उचित समझे ।

शक्तियां और
कृत्य।

4. (1) संसदीय सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) संसदीय सचिव को, प्रभारी मन्त्री के विचार हेतु नस्ति पर प्रस्ताव के प्ररूप में अपना टिप्पण अभिलिखित करने के सिवाय, सचिव या सरकार के किसी अन्य अधीनस्थ कृत्यकारी द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई को अनुमोदित करने की शक्तियां नहीं होगी ।

विशेषाधिकार
और
सुख—
सुविधाएं ।

5. संसदीय सचिव ऐसे विशेषाधिकार और ऐसी सुख—सुविधाओं का हकदार होगा, जैसी सदस्यों को उपलब्ध हैं ।

पद की और
गोपनीयता
की शपथ ।

6. किसी संसदीय सचिव द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पूर्व मुख्य मन्त्री उसे निम्नलिखित रीति में पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा:—

“मैं, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्त्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा ।”

वेतन और
भत्ते।

7. मुख्य संसदीय सचिव प्रति मास ग्यारह हजार रुपए वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा जबकि संसदीय सचिव प्रतिमास दस हजार रुपए वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, संसदीय सचिव ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते तथा अन्य परिलब्धियां प्राप्त करने का हकदार होगा जैसी सदस्यों को अनुज्ञेय हैं ।

8. (1) प्रत्येक संसदीय सचिव को, एक सुसज्जित गृह दिया निवास जाएगा, जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया स्थान। जाएगा या ऐसे गृह के स्थान पर, निम्नलिखित दरों पर भत्ता संदत्त किया जाएगा; अर्थात्:-

(क) मुख्य संसदीय सचिव तीन हजार रुपए प्रति मास;
और

(ख) संसदीय सचिव दो हजार पांच सौ रुपए प्रति
मास।

(2) राज्य सरकार संसदीय सचिव को दिए गए गृह को उसे, संसदीय सचिव न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए, अधिभोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी।

(3) प्रत्येक संसदीय सचिव, उसे आबंटित सुसज्जित गृह के बारे में, उसके वेतन के दस प्रतिशत की दर से लाइसेंस फीस संदत्त करने का दायी होगा और वह उसके वेतन से प्रति मास वसूलीय होगी।

स्पष्टीकरण.— संसदीय सचिव ऐसे किसी मामले में जहां उसको आवास के लिए आबंटित गृह का मानक किराया उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक हो, किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

9. प्रत्येक संसदीय सचिव एक कार का, जिसके अनुरक्षण वाहन और नोदन का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी या उसके स्थान पर भत्ता। तीन सौ रुपए प्रतिमास की दर से वाहन भत्ते का, हकदार होगा।

10. इस अधिनियम के अधीन वेतन या भत्ते प्राप्त करने वाला कोई संसदीय भी संसदीय सचिव सदस्य के रूप में वेतन या भत्तों के तौर पर कोई भी राशि सचिव द्वारा सदस्य के रूप में वेतन या भत्तों का न लेना।

संसदीय सचिव द्वारा कोई वृत्ति आदि न करना।

11. कोई भी संसदीय सचिव अपने इस पद के दौरान, ऐसे संसदीय सचिव के कर्तव्यों से अन्यथा, कोई भी वृत्ति नहीं करेगा या किसी व्यापार या वाणिज्य में नहीं लगेगा या पारिश्रमिक के लिए कोई भी नियोजन अपने हाथ में नहीं लेगा।

नियम बनाने की शक्ति।

12. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या उपरोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या सहमत हो जाती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसा नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि ऐसे किसी परिवर्तन या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः मुख्य संसदीय सचिवों या संसदीय सचिवों की नियुक्ति के लिए कोई वैधानिक उपबन्ध नहीं है, उनकी नियुक्तियां परम्परागत आधार पर की गई थी। इन नियुक्तियों के उद्देश्य संसदीय कार्यों को प्रबलता प्रदान करने, संसदीय/विधायी कार्यों के प्रबन्धन को अत्याधिक और अधिक दक्ष तथा प्रभावी बनाने तथा मन्त्रियों के अत्याधिक कार्यभार को कम करने और भविष्य में किशोरावस्था के सदस्यों को उच्चतर उत्तरदायित्वों को सांझा करने के अवसर भी प्रदान करने के द्वियुग्म प्रयोजन की पूर्ति करना है। इसलिए ऐसा विधान लाने का विनिश्चय किया गया है जो हिमाचल प्रदेश राज्य में संसदीय सचिवों की नियुक्ति, वेतन, भत्तों, शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा सुख-सुविधाओं आदि का उपबन्ध कर सकेगा।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख : 2006.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3, 5 और 7 से 9 के अधिनियमित होने पर राजकोष से अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 12 राज्य सरकार को विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है । शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(सामान्य प्रशासन विभाग नस्ति संख्या:जी.ए.डी.-सी. डी (6)-3/2006)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख-सुविधाएं) विधेयक, 2006 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को राज्य विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

**हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार
और सुख-सुविधाएं) विधेयक, 2006**

हिमाचल प्रदेश राज्य में संसदीय सचिवों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियों, विशेषाधिकारों
और सुख-सुविधाओं का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

डॉ० जे० एन० बारोवालिया,
सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख : 2006.

**THE HIMACHAL PRADESH PARLIAMENTARY
SECRETARIES (APPOINTMENT, SALARIES,
ALLOWANCES, POWERS, PRIVILEGES AND
AMENITIES) BILL, 2006**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities etc. of the Parliamentary Secretaries in the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Chief Minister” means the Chief Minister of Himachal Pradesh;
- (b) “member” means a member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh;
- (c) “notification” means a notification published under proper authority in the Official Gazette;
- (d) “Parliamentary Secretary” means a member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh appointed as the Parliamentary Secretary or the Chief Parliamentary Secretary under section 3 of this Act;
- (e) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Act; and
- (f) “specified” means specified by notification published in the Official Gazette.

3. The Chief Minister may appoint such number of the Parliamentary Secretaries, and assign to each of them such duties and functions, as he may deem fit. Appointment.

4. (1) A Parliamentary Secretary shall exercise such powers, discharge such functions and perform such duties as may be specified by the Chief Minister. Powers and functions.

(2) A Parliamentary Secretary shall not have the powers to approve the action proposed by a Secretary or any other subordinate functionary of the Government, except recording his note in the form of proposal on the file for the consideration of the Minister-In-Charge.

5. A Parliamentary Secretary shall be entitled to such privileges and amenities as available to the members. Privileges and amenities.

6. Before a Parliamentary Secretary enters upon his office, the Chief Minister shall administer to him oath of office and secrecy in the following manner:— Oath of office and secrecy.

“I, _____, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Parliamentary Secretary for the State except as may be required for the due discharge of my duties as such Parliamentary Secretary.”

7. A Chief Parliamentary Secretary shall be entitled to the salary of Rs. 11,000/- per month, while a Parliamentary Secretary shall be entitled to a salary of Rs. 10,000/- per month. In addition, the Parliamentary Secretary shall be entitled to compensatory allowance and other perquisites as are admissible to the members. Salaries and allowances.

8. (1) A Parliamentary Secretary shall be provided with a furnished house, the maintenance charges of which shall be borne by the State Government or in lieu of such house, shall be paid an allowance at the following rates, namely:— Residence.

| | | |
|------------|--|--|
| (a) | a Chief Parliamentary Secretary | Rupees three thousand per mensem; and |
|------------|--|--|

(b) a Parliamentary
Secretary

Rupees two thousand and five
hundred per mensem.

(2) The State Government may allow Parliamentary Secretary to continue in occupation of the house provided to him for a period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be a Parliamentary Secretary.

(3) A Parliamentary Secretary shall be liable to pay licence fee at the rate of 10% of his salary in respect of the furnished house allotted to him and the same shall be recoverable monthly from his salary.

Explanation.— A Parliamentary Secretary shall not become personally liable for any payment in case the standard rent of the house allotted to him for residence exceeds the amount specified in sub-section (1).

Conveyance
allowance.

9. A Parliamentary Secretary shall be entitled to the use of a car, the expenses on the maintenance and propulsion of which shall be borne by the State Government or in lieu thereof to a conveyance allowance at the rate of rupees three hundred per mensem.

Parliamentary
Secretary
not to draw
salary or
allowances
as member.

10. No Parliamentary Secretary, in receipt of a salary or allowances under this Act, shall be entitled to receive any sum by way of salary or allowances as member.

Parliamentary
Secretary not
to practise
profession
etc.

11. A Parliamentary Secretary shall not, during his office as such, practise any profession or engage in any trade or commerce or undertake for remuneration any employment other than his duties as such Parliamentary Secretary.

Power to
make the
rules.

12. (1) The State Government may, by notification published in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present there is no statutory provision for appointment of the Chief Parliamentary Secretaries or the Parliamentary Secretaries and earlier their appointments were made on conventions. The object behind the appointment of the Chief Parliamentary Secretaries and the Parliamentary Secretaries is to strengthen Parliamentary affairs and make the system more efficient and effective and to serve the twin purpose of lightening the over burden of Ministers and also to afford opportunity to youth members to share higher responsibilities in future. As such, it has been decided to bring a legislation which may provide for appointment, salaries, allowances, powers, privileges and amenities of the Parliamentary Secretaries in the State of Himachal Pradesh.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA:

The _____ December, 2006.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 3, 5 and 7 to 9 of the Bill, if enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer which can not be quantified.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 12 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(GAD File No. GAD-C-D (6)-3/2006)

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Bill, 2006, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in State Legislative Assembly.

**THE HIMACHAL PRADESH PARLIAMENTARY SECRETARIES
(APPOINTMENT, SALARIES, ALLOWANCES, POWERS,
PRIVILEGES AND AMENITIES) BILL, 2006**

A

BILL

to provide for the Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities of the Parliamentary Secretaries in the State of Himachal Pradesh.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

DR. J. N. BAROWALIA,
Secretary (Law).

SHIMLA:

The _____ December, 2006.

